

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission)

उद्देश्य-क्वांटम प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास में शामिल शीर्ष छह अग्रणी देशों में भारत को शामिल करना

■ वर्तमान में क्वांटम प्रौद्योगिकियों अनुसंधान एवं विकास कार्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चैन और ऑस्ट्रिया में जारी ■

■ अवधि: 2023-24 से 2030-31

■ नोडल मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

■ मिशन की प्रमुख बातें:

■ देश भर में विभिन्न डोमेन में चार थीम आधारित हब (T-Hubs)

■ स्वास्थ्य देखभाल एवं निदान, रक्षा ऊर्जा और डेटा सुरक्षा तक व्यापक पैमाने पर अनुप्रयोग

■ स्वदेश निर्मित क्वांटम आधारित कंप्यूटर का सुदृढ़ीकरण

■ परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मेट्रोमीटर विकसित करने में सहायता करना

■ क्वांटम पदार्थों के डिजाइन तथा संश्लेषण का समर्थन

डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और SDG जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भारी बढ़ावा

क्वांटम प्रौद्योगिकी

■ क्वांटम एनटैंगलमेंट तथा क्वांटम सुपरपोजिशन सहित क्वांटम यांत्रिकी (उप-परमाणु कणों की भौतिकी) के सिद्धांतों की सहायता से काम करती है। ■

क्वांटम सुपरपोजिशन

किसी क्वांटम प्रणाली की एक साथ कई अवस्थाओं में होने की क्षमता

जबकि डिजिटल कंप्यूटर डेटा को बिट्स (बाइनरी के वाले और शून्य) के रूप में संग्रहीत करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर उन क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक ही समय में एक शून्य या दोनों के रूप में मौजूद होते हैं।

यद्यपि डिजिटल कंप्यूटर डेटा को बिट्स (बाइनरी की एका और शून्य) के रूप में संग्रहीत करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर उन क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक ही समय में एक शून्य या दोनों के रूप में मौजूद होते हैं।

यह सुपरपोजिशन स्थिति संभावनाओं की एक व्यावहारिक रूप से अनंत सीमा का निर्माण करती है, जिससे तेजी से एक साथ और समानांतर गणना की अनुमति मिलती है।

क्वांटम एनटैंगलमेंट

■ इसका मतलब है कि एक जोड़ी (क्यूबिट्स) के दो सदस्य एक ही क्वांटम अवस्था में मौजूद हैं।

■ यदि आप उनमें से एक के गुणों को बदलते हैं, तो दूसरा भी तुरंत बदल जाता है।

■ इसका उपयोग क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में एक सुरक्षित एन्क्रिप्शन कुंजी बनाने के लिये किया जा सकता है।

■ यदि प्रच्छन्नश्रावी (eavesdropper) संबरण को रोकने का प्रयास करता है, तो कणों की उलझी हुई स्थिति अशांत जाएगी, जिससे इस तरह के प्रयास का पता लगाया जा सकेगा।



प्रलम्बिस के लयि:

शहरी स्थानीय नकिय, महिलाओं के लयि आरकषण

मेन्स के लयि:

संवधिन के अनुच्छेद 371A दवारा नगालैंड को प्राप्त वशिष प्रावधान, भारत में शहरी स्थानीय नकियों (ULB) की संरचना और कार्य

चर्चा में क्यों?

शहरी स्थानीय नकिय (ULB) चुनावों में महिलाओं के लयि सीटों के आरकषण को लेकर नगालैंड में हालयि वविद के कारण राज्य में वभिन्न हतिधारकों के बीच बहस शुरू हो गई है।

- यह मुददा नगालैंड नगरपालिका अधनियम, 2001 पर केंद्रति है जसिके तहत भारतीय संवधिन के 74वें संशोधन के अनुसार ULB चुनावों में महिलाओं के लयि 33% आरकषण अनविर्य है।

74वाँ संवधिन संशोधन अधनियम:

- वर्ष 1992 में पी.वी. नरसमिहा राव की सरकार के दौरान 74वें संशोधन अधनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कयि गया था। यह 1 जून, 1993 को लागू हुआ।
 - इसमें भाग IX-A जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243-P से लेकर 243-ZG तक प्रावधान शामिल हैं।
 - इसके अतरिकित इस अधनियम के तहत संवधिन में 12वीं अनुसूची को भी शामिल कयि गया। इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक वषिय शामिल हैं।

ULB चुनावों में महिला आरकषण का नगालैंड के वरिध का कारण:

- महिलाओं के लयि आरकषण का वषिय परंपरा के खलिफ:
 - अधकिंश पारंपरिक आदवासी और शहरी संगठन महिलाओं के लयि सीटों के 33% आरकषण का वरिध करते हैं, उनका तर्क है कयिह संवधिन के अनुच्छेद 371A दवारा नगालैंड को प्रदान कयि गए वशिष प्रावधानों का उल्लंघन है।
 - अनुच्छेद 371A के अनुसार, नगालैंड वधिनसभा की सहमति के बनिा, संसद नगाओं के सामाजिक अथवा धार्मिक रीति-रिवाजों, कानूनी वविदों को हल करने के उनके प्रथागत कानूनों और प्रक्रियाओं को प्रभावति करने वाले कानूनों को पारति नहीं कर सकती है।
 - नगालैंड के शीर्ष आदवासी नकिय, नगा होहो का तर्क है कयि महिलाएँ पारंपरिक रूप से नरिणय लेने वाली संस्थाओं का हसिसा नहीं रही हैं।
 - नगालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ ULB की सीटें महिलाओं के लयि आरकषति नहीं हैं।
- प्रदर्शनकारियों की मांग:
 - आदवासी नकियों और नागरिक समाज संगठनों ने तब तक चुनावों का बहषिकार करने की धमकी दी है जब तक कयि नगरपालिका अधनियम, 2001 में महिला आरकषण को ध्यान में रखते हुए "नगा लोगों की मांग की पूरी तरह से समीक्षा और पुनरलेखन नहीं कयि जाता है" ताकयिह अनुच्छेद 371A का उल्लंघन न करे।
- नगालैंड में पछिला ULB चुनाव:
 - नगालैंड में पहला और एकमात्र नकिय चुनाव 2004 में महिलाओं के लयि सीटों के आरकषण के बनिा आयोजति कयि गया था।
 - वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने महिलाओं के लयि 33% आरकषण को शामिल करने हेतु नगरपालिका अधनियम 2001 में संशोधन कयि, जसिका व्यापक वरिध हुआ और परणामस्वरूप वर्ष 2009 में ULB चुनावों को अनश्चिति काल के लयि स्थगति कर दयि गया था।
 - मार्च 2012 में चुनाव कराने के प्रयासों का भी व्यापक वरिध हुआ, साथ ही सतिंबर 2012 में राज्य वधिनसभा ने नगालैंड को महिलाओं हेतु आरकषण से संबंधति संवधिन के अनुच्छेद 243T से छूट देने का प्रस्ताव पारति कयि।
 - इस प्रस्ताव को वर्ष 2016 में रद्द कर दयि गया था और 33 प्रतिशत आरकषण के साथ नागरिक नकियों के चुनावों को एक महीने बाद अधसूचिति कयि गया जसि कारण फरि से व्यापक अशांति देखी गई।
 - सरकार ने फरवरी 2017 में चुनावों को शून्य और नरिस्त घोषति करने की प्रक्रिया की घोषणा की।

शहरी स्थानीय नकिय (ULB):

- वषिय:
 - शहरी स्थानीय नकिय (ULBs) छोटे स्थानीय नकिय हैं जो एक नरिदषिट आबादी वाले शहर या कस्बे को प्रशासति या नरियंत्रति करते हैं।
 - ULBs के अधिकार क्षेत्र में संबंधति राज्य सरकारों दवारा सौंपे गए कार्यों की एक लंबी सूची है जसिमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण, नयामक कार्य, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक बुनयादी ढाँचे और वकिस गतविवधियाँ आदि शामिल हैं।

हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन (DAY-NRLM) ने "संगठन से समृद्धि-किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना (Sangathan Se Samridhhi- Leaving no Rural Woman Behind)" अभियान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups- SHG) के अंतर्गत सभी कमज़ोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को लाना है।

संगठन से समृद्धि अभियान:

■ परिचय:

- यह अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के अंतर्गत लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को संगठित करना है।
- इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत सभी कमज़ोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को लाना है, ताकि वे ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किये जा रहे लाभों को प्राप्त कर सकें।
- यह अभियान 1.1 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने की वचिार के साथ सभी राज्यों में चलाया जाएगा। इसके तहत प्रस्तावित कार्य इस प्रकार हैं:
 - ग्राम संगठनों की सामान्य बैठकें आयोजित करना।
 - स्वयं सहायता समूह चैपियनों द्वारा अनुभव साझा करते हुए परिवारों को इसमें शामिल करने के लिये प्रेरित करना।
 - सामूहिक संसाधन व्यक्ति अभियान (Community Resource Person drives) का आयोजन
 - स्वयं सहायता समूह बैंक खाते खोलना तथा अन्य हितधारकों द्वारा संवर्द्धित SHG का सामान्य डाटाबेस तैयार करना।

■ ऐसे अभियान की आवश्यकता:

- भारत की कुल आबादी का 65% ग्रामीण आबादी है और इन क्षेत्रों की महिलाओं को भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने हेतु सभी संभव अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
- जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएँ SHG का हिस्सा बनेंगी, तो इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

महिला सशक्तीकरण में SHGs की भूमिका:

■ आर्थिक सशक्तीकरण:

- SHGs महिला उद्यमियों को उनके व्यवसायों को बनाए रखने हेतु सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं, साथ ही उनके लिये अधिक अभिकर्तृत्व एवं नरिणय लेने के कौशल विकसित करने हेतु एक बेहतर वातावरण भी बनाते हैं।
 - इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रसिर्च (IFMR) द्वारा वर्ष 2022 के एक अध्ययन के अनुसार, SHGs द्वारा सहायता प्राप्त महिलाओं की नयिमति रूप से बचत करने की संभावना 10% अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप अगली पीढ़ी के लिये बेहतर भविष्य की दशा में काम करते हुए आर्थिक सशक्तीकरण हुआ।

■ महिला उद्यमिता:

- SHGs महिला उद्यमियों हेतु उद्यमशीलता प्रशिक्षण, आजीविका संवर्द्धन एवं सामुदायिक विकास से लेकर अन्य सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।
- अकेले महाराष्ट्र में 527,000 SHGs हैं, जो भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाली सभी छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों का 50% से अधिक हिस्सा है।
 - यह एक स्पष्ट संकेत है कि SHGs महिला उद्यमिता के समग्र विकास का नेतृत्व कर सकते हैं।

■ कौशल विकास:

- स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का कार्य भी करते हैं। महिलाएँ सिलाई, हस्तशिल्प या खेती की तकनीक जैसे नए कौशल सीख सकती हैं।
- इससे न केवल उन्हें अपनी आय क्षमता में सुधार करने में मदद मिलती है बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान में भी वृद्धि होती है।

■ सामाजिक अधिकारिता:

- स्वयं सहायता समूह महिलाओं को एक साथ आने और अपने अनुभव साझा करने के लिये एक मंच प्रदान करते हैं। इससे महिलाओं में एकजुटता की भावना पैदा होती है तथा सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मदद मिलती है।
- यह महिलाओं को घरेलू और सामुदायिक स्तर पर नरिणय लेने में भागीदार बनने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें एक पहचान मिलती है और उनका जीवन पर अधिक नयितरण होता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन:

■ वषिय:

- यह वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक केंद्र परायोजित कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य देश भर में ग्रामीण गरीब परिवारों के लिये अनेक प्रकार की आजीविकाओं को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को खत्म करना है।

■ कार्य पद्धति:

- इसमें स्वयं सहायता की भावना से सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से सामुदायिक संस्थानों के साथ कार्य करना शामिल है जो DAY-NRLM का एक अनूठा प्रस्ताव है।

○ यह आजीविका को प्रभावित करता है, जैसे:

- ग्रामीण परिवारों को SHGs में संगठित करना।
- **प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार** से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना।
- **SHG सदस्यों को प्रशिक्षण** और क्षमता निर्माण में सहायता करना।
- अपने स्वयं के संस्थानों और बैंकों से वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना।

■ **उप कार्यक्रम:**

- **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना:** इसका उद्देश्य ऐसे कृषि-परिस्थितिकि प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो महिला किसानों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी इनपुट लागत और जोखिम को कम करते हैं।
- **स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP):** इसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमों की स्थापना के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है।
- **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY):** AGEY को अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, जिसके तहत दूरदराज़ के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिये सुरक्षा, सस्ती और सामुदायिक नगिरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY):** इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्लेसमेंट से जुड़े कौशल प्रदान करना ताकि वे अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत उच्च मज़दूरी वाले रोज़गार प्राप्त कर सकें।
- **ग्रामीण स्वरोज़गार संस्थान (RSETIs):** DAY-NRLM, 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोज़गार स्थापित करने हेतु कुशल बनाने के लिये ग्रामीण स्वरोज़गार संस्थानों (RSETIs) को सहायता प्रदान कर रहा है।

■ **परिणाम:**

- जुलाई 2022 तक 8.35 करोड़ महिलाएँ NRLM से जुड़ी थीं और बैंकों के 5.9 लाख करोड़ रुपए जुड़े थे, जबकि NPA घटकर 2.5% रह गया है।
 - इस योजना में वर्ष 2014 तक 2.35 लाख घरों को शामिल किया गया था जिसमें 9.58% **कीमती-निष्पादित संपत्ति (Non-Performing Assets- NPA)** के साथ बैंकों द्वारा 80,000 करोड़ रुपए दिये गए थे।
- मई 2021 तक भारत में 7,83,389 गाँवों में 75 मिलियन सदस्यों के साथ 6.9 मिलियन SHG हैं।
- NRLM ने ग्रामीण परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं तक अधिक पहुँच हेतु सक्षम बनाया है।
 - **इसने खाद्य सुरक्षा और स्कूलों में नामांकन में सुधार किया है, महिलाओं को खाद्यान्न उत्पादन हेतु भूमितिक पहुँच प्रदान की है** तथा दहेज, बाल विवाह एवं लड़कियों के खिलाफ भेदभाव जैसे मुद्दों पर महिला समूहों पर प्रभाव डाला है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन ग्रामीण क्षेत्रीय नरिधनों के आजीविका वकिल्पों को सुधारने का कसि प्रकार प्रयास करता है? (2012)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए वनिरमाण उद्योग तथा कृषिव्यापार केंद्र स्थापति कर।
2. 'स्व-सहायता समूहों' को सशक्त बनाकर और कौशल वकिस की सुवधिएँ प्रदान कर।
3. कृषकों को नःशुल्क बीज, उर्वरक, डीज़ल पंपसेट तथा लघु सचिएँ सयंत्र देकर।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. "वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूहों का उदभव राज्य के वकिसात्मक गतविधियिों से धीमे परंतु नरितर पीछे हटने का संकेत है"। वकिसात्मक गतविधियिों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहति करने के लिये कयि गए उपायों का परीक्षण कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2017)

प्रश्न. आत्मनरिभर समूह (एस.एच.जी.) बैंक अनुबंधन कार्यक्रम (एस.बी.एल.पी.), जो कि भारत का स्वयं का नवाचार है, नरिधनता न्यूनीकरण और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों में एक सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम साबति हुआ है। सवसितार स्पष्ट कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2015)

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत-UAE खाद्य सुरक्षा साझेदारी

प्रलिस के लिये:

खाद्य सुरक्षा, पोषण अभियान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, [I2U2 शिखर सम्मेलन 2022](#), व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), पोषक अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष।

मेन्स के लिये:

भारत-UAE खाद्य सुरक्षा साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र, वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिये प्रमुख चुनौतियाँ।

चर्चा में क्यों?

[संयुक्त अरब अमीरात \(UAE\)](#), जिसकी [खाद्य सुरक्षा](#) वैश्विक बाजारों से होने वाले आयात पर निर्भर है, अब आपूर्ति शृंखला संकट का सामना करने के लिये खाद्य पहुँच और तत्परता के दोहरे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है और खाद्य सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करने की संयुक्त अरब अमीरात की महत्वाकांक्षा के लिये एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
- भारत-UAE खाद्य सुरक्षा साझेदारी अभिसरण के कई बड़ों से लाभान्वित होती है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा साझेदारी को मज़बूत करने की दशा में भारत-संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका:

- भारत की क्षमता:
 - कृषि-निर्यात पर मज़बूत पकड़:
 - प्रचुर कृषि योग्य भूमि, अनुकूल जलवायु और बढ़ता खाद्य उत्पादन तथा प्रसंस्करण क्षेत्र के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर [कृषि-निर्यात](#) के प्रमुखतम स्रोत के रूप में भारत की स्थिति मज़बूत है।
 - मानवीय सहायता:
 - भारत क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए विकासशील देशों को मानवीय खाद्य सहायता प्रदान करने में भी शामिल रहा है।
 - फूड पार्क और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन:
 - भारत ने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों से लाभान्वित होने के लिये [फूड पार्क](#) और आधुनिक आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जो वैश्विक खाद्य बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने इरादे को प्रदर्शित करता है।
 - सरकारी पहल:
 - भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम - [सार्वजनिक वितरण प्रणाली](#) चलाता है, लगभग 800 मिलियन नागरिकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराता है, दैनिक भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
 - भारत का [पोषण अभियान](#) बच्चों और महिलाओं के लिये विश्व का सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम है, जो खाद्य सुरक्षा में पोषण के महत्त्व पर जोर देता है।
- UAE's का योगदान:
 - निवेश:
 - UAE ने [I2U2 शिखर सम्मेलन 2022](#) के दौरान भारत में फूड पार्कों के निर्माण के लिये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
 - खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर:
 - संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक खाद्य मूल्य शृंखला में भारत की उपस्थिति को और अधिक बढ़ाते हुए [व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते \(CEPA\)](#) के साथ-साथ एक खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किये हैं।
 - एग्रीओटा:
 - दुबई मल्टी कमोडिटीज़ सेंटर ने कृषि-व्यापार और कमोडिटी प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है, जो भारतीय किसानों को UAE के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ता है तथा अमीरात के बाजारों तक सीधी पहुँच में सक्षम बनाता है।
- महत्त्व:
 - भारत के लिये नए बाजारों का प्रवेश द्वार:
 - एशिया और यूरोप के बीच संयुक्त अरब अमीरात का रणनीतिक स्थान पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के लिये भारत के खाद्य निर्यात प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है, जो अपने खाद्य भंडार को बनाए रखने तथा उसमें विविधता लाकर लाभ प्रदान कर सकता है।
 - भारत, संयुक्त अरब अमीरात की नज़ी क्षेत्र की परियोजनाओं, गैर-कृषि-रोज़गार पैदा करने और किसानों के उत्पादों का बेहतर मूल्य प्रदान कर लाभान्वित होने के लिये तत्पर है।
 - वैश्विक खाद्य सुरक्षा भागीदारी के लिये संरचना:
 - भारत की [G-20 अध्यक्षता](#) ग्लोबल साउथ में खाद्य सुरक्षा के लिये सफल रणनीतियों और रूपरेखाओं को प्रदर्शित करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करती है।

- भारत खाद्यान्न के एक **स्थायी, समावेशी, कुशल और लचीले भविष्य** के निर्माण के लिये UAE के साथ समुद्री व्यापार मार्गों का लाभ उठा सकता है और स्थिति को मजबूत कर सकता है क्योंकि यह **वैश्विक विकास एजेंडा** निर्धारित करता है।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- जलवायु परिवर्तन का खतरा: **संयुक्त राष्ट्र** ने **जलवायु परिवर्तन** तथा चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ती खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारक बताया है।
 - बढ़ते तापमान, मौसम की परिवर्तनशीलता, आक्रामक फसलें एवं कीट तथा लगातार बढ़ते चरम मौसमी घटनाओं का खेती पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में कमी तथा खेतों की उत्पादकता व पोषण गुणवत्ता कमज़ोर होती है जो अंततः किसानों की आय में कमी का कारण बनता है।
- अस्थिर बाज़ार मूल्य: **वैश्वीकरण** की अवधारणा ने कृषि बाजारों को अधिक खुलापन प्रदान किया है, लेकिन यह अधिक स्थिर बाज़ार मूल्य निर्धारण का आश्वासन देने में असमर्थ है।
 - अंतर्गत वस्तुओं हेतु लाभकारी कीमतों की कमी, संकटग्रस्त बकिरी, अनुपयुक्त बाज़ार कीमतों के साथ संयुक्त उच्च कृषि लागत खाद्य सुरक्षा के मार्ग में बाधा के रूप में कार्य करती है।
- व्यापार व्यवधान: **भू-राजनीतिक तनाव एवं व्यापार विवादों** के परिणामस्वरूप व्यापार में व्यवधान आ सकता है, जिसमें व्यापार प्रतिरোধ, प्रतिबंध एवं टैरिफ शामिल हैं, जो खाद्य व्यापार तथा खाद्य कीमतों एवं उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं।
 - यह विशेष रूप से उन देशों को प्रभावित कर सकता है जो खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, इससे खाद्य की कमी एवं खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे कमज़ोर आबादी हेतु भोजन कम सुलभ हो पाता है।

आगे की राह

- जलवायु लचीलापन बढ़ाना: जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण एवं जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों जैसे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन उपायों में निवेश, खाद्य उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है।
- जलवायु अनुकूल फसलों को प्रोत्साहन: जलवायु-लचीली फसलों के विकास एवं वितरण के लिये निवेश की आवश्यकता है जो तापमान भिन्नता और वर्षा में उतार-चढ़ाव को सहन कर सके।
 - सरकारों को जल और पोषक तत्व-कुशल फसलों (जैसे बाज़रा और दालें) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ ही किसानों के लिये आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा इनपुट सब्सिडी की घोषणा करनी चाहिये।
 - **संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा** द्वारा अपने 75वें सत्र में **वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष** घोषित किया जाना इस दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- कृषि कूटनीति: भारत अफ्रीका और एशिया के अन्य विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी साझेदारी, सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देने में संयुक्त अनुसंधान, जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के माध्यम से अपने समर्थन में वृद्धि कर सकता है जिससे भारत को **वैश्विक दक्षिण** के एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित होने में मदद मिल सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

2021-22:

प्रश्न. जलवायु अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत में जलवायु-स्मार्ट ग्राम (जलवायु-स्मार्ट वल्लिज) दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम- जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा (CCAFS) द्वारा संचालित एक परियोजना का भाग है।
2. CCAFS परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (CGIAR) के अधीन संचालित किया जाता है जिसका मुख्यालय फ्रांस में है।
3. भारत में स्थिति अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उपकटबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो 'गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.)' की श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत किये जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छह महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेश व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, कति इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टपिपणी कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2015)

स्रोत: द हिंदू

यमन में शांति की उम्मीद

प्रलमिस के लिये:

हौथसि, यमन का क्षेत्र और पड़ोस, ऑपरेशन राहत

मेन्स के लिये:

यमन गृह युद्ध, हौथी संघर्ष का महत्त्व, भारत की रुचि

चर्चा में क्यों?

यमन में युद्धरत पक्ष सैकड़ों कैदियों की अदला-बदली कर रहे हैं, जसिनेसऊदी समर्थति सरकारी बलों और ईरान समर्थति हौथी वदिरोहियों के बीच एक स्थायी युद्धवशिम की उम्मीद जगाई है।



यमन में युद्ध की शुरुआत:

- यमन गृह युद्ध 2011 में सत्तावादी राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह (Ali Abdullah Saleh) के अपदस्थ होने के बाद शुरू हुआ। नए राष्ट्रपति, अब्दरबुह मंसूर हादी, आर्थिक और सुरक्षा समस्याओं के कारण देश को स्थिरता प्रदान करने में असमर्थ रहे।
- जैदी शिया मुसलमि अल्पसंख्यक समूह हौथिसि ने इसका फायदा उठाया और वर्ष 2014 में उत्तर और राजधानी सना पर नियंत्रण कर लिया।
 - इसने सऊदी अरब को चिंतित कर दिया, जिससे डर था कि हौथिसि उनके प्रतिद्वंद्वी ईरान के सहयोगी बन जाएंगे। सऊदी अरब ने तब एक गठबंधन का नेतृत्व किया जिसमें अन्य अरब देश शामिल थे और वर्ष 2015 में यमन में सेना भेजी। हालाँकि सना के साथ-साथ देश के उत्तर से हौथियों को खदेड़ने में असमर्थ थे।
 - अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन और हौथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष वरिष्ठ की मध्यस्थता की, हालाँकि पक्षकार छह महीने बाद इसे नवीनीकृत करने में विफल रहे।

स्टॉकहोम समझौता:

- यमन के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखने वाले युद्धरत पक्षों ने दिसंबर 2018 में संघर्ष-संबंधी बंदियों को मुक्त करने के लिये स्टॉकहोम समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा मध्यस्थता किये गए समझौते के तीन मुख्य घटक थे:
 - हुदायाह समझौता:
 - हुदायाह समझौते में होदेइदाह शहर में युद्धविराम और शहर में कोई सैन्य सुदृढ़ीकरण न होने जैसे अन्य खंड शामिल थे और संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति को मज़बूत किया गया था।
 - कैदी वनिमिय समझौता:
 - अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इस प्रक्रिया की देख-रेख और समर्थन करेगी, जिसकी देख-रेख यमन के महासचिव के विशेष दूत के कार्यालय द्वारा की गई थी।
 - उनका उद्देश्य मौलिक मानवीय संधिधर्मों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना है जो यमन में घटनाओं के दौरान अपनी स्वतंत्रता से वंचित सभी व्यक्तियों की रहिआई या स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करते हैं।
 - ताइज़ समझौता:
 - ताइज़ समझौते में नागरिक समाज और संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी के साथ एक संयुक्त समिति का गठन शामिल है।

इस युद्ध का यमन पर प्रभाव:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यमन में अब दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट है, जिसकी 80% आबादी सहायता और सुरक्षा पर निर्भर है।
- वर्ष 2015 से 30 लाख से अधिक लोग अपने घरों से वसिस्थापित हुए हैं और स्वास्थ्य सेवा, जल, स्वच्छता एवं शिक्षा जैसे सार्वजनिक सेवा

क्षेत्र या तो समाप्त हो गए हैं या गंभीर स्थिति में हैं।

- यमन आर्थिक रूप से संकट में है, आर्थिक उत्पादन में 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है, साथ ही 6,00,000 से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। देश की आधी से ज्यादा आबादी व्यापक गरीबी में जी रही है।

यमन संकट के कारण भारत और विश्व की चिंताएँ:

■ वैश्विक:

- अंतर्राष्ट्रीय तेल शिपमेंट के लिये अदान की खाड़ी से [लाल सागर](#) को जोड़ने वाले जलसंधि में यमन का अवस्थिति होना यह चिंता उत्पन्न करता है कि यमन संकट विश्व भर में तेल की कीमतों को किस प्रकार प्रभावित करेगा।
- यमन में अल-कायदा और IS से जुड़े समूहों की उपस्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिये जोखिम पैदा करती है।

■ भारत:

- यमन भारत के लिये कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत है और तेल आपूर्ति शृंखला में कोई भी व्यवधान भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
 - यमन, सऊदी अरब, ईरान में रह रहे भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी भारत के लिये एक चुनौती है।
 - भारत पर अपने नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने एवं प्रेषित धन (Remittances) में किसी भी व्यवधान के प्रभाव का प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी है, जो भारत में कई परिवारों के लिये आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

भारत की पहलें:

■ ऑपरेशन राहत:

- भारत ने अप्रैल 2015 में यमन से 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिये बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री अभियान शुरू किये।

■ मानवीय सहायता:

- भारत ने अतीत में यमन को भोजन एवं चिकित्सा सहायता प्रदान की है तथा वगित कुछ वर्षों में हजारों यमन- नागरिकों ने भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाया है।
- भारत विभिन्न भारतीय संस्थानों में बड़ी संख्या में यमन- नागरिकों को शिक्षा की सुविधा भी प्रदान करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में नमिनलखिति में से कनि देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध/संजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण मृत्यु हुई? (2018)

- (a) अंगोला और ज़ाम्बिया
- (b) मोरक्को और ट्यूनीशिया
- (c) वेनेज़ुएला और कोलंबिया
- (d) यमन और दक्षिण सूडान

उत्तर: (d)

[स्रोत: द हिंदू](#)

पशु जन्म नियंत्रण नयिम, 2023

प्रलमिस के लयि:

[पशु कुरुरता नविरण अधनियिम, 1960](#), [भारतीय पशु कल्याण बोरड](#), [रेबीज़](#), [राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र](#), [वन हेल्थ](#)।

मेन्स के लयि:

भारत में रेबीज़ की स्थिति, पशु जन्म नियंत्रण नयिम, 2023।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 जारी किया है। यह नियम पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का स्थान लेगा, जिसे [पशु कुररता नविवरण अधिनियम, 1960](#) के तहत जारी किया गया है

पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023:

■ पृष्ठभूमि:

- नवंबर 2022 तक संसद में पेश किये गए आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 और 2022 के बीच भारत में स्ट्रीट डॉग/ कुत्तों के काटने के 160 मिलियन मामले दर्ज किये गए।
- जसिसे कुत्ते के मालिक, कुत्ते के भोजन और देखभाल करने वालों के खिलाफ प्रतियोध के कृत्यों के साथ-साथ शहरी नविसायियों के बीच संघर्ष भी बढ़ गया है।

■ प्रावधान:

- नयिमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा [भारतीय पशु कल्याण बोर्ड](#) और आवारा पशुओं को होने वाली परेशानियों के उनमूलन के लिये लोगों से संबंधित दशिया-नरिदेशों के अनुसार तैयार किया गया है।
 - [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वभिन्न आदेशों में वशिष रूप से उल्लेख किया है कि कुत्तों के स्थानांतरण की अनुमतनिहीं दी जा सकती है।
- नयिमों का उद्देश्य पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिये दशिया-नरिदेश प्रदान करना है।
 - एबीसी कार्यक्रमों को चलाने की ज़मिमेदारी संबंधित स्थानीय नकियायों, नगर पालकियाओं, नगर नगिमों और पंचायतों की है।
 - नगर नगिमों को ABC और एंटी रेबीज़ कार्यक्रम को संयुक्त रूप से लागू करने की आवश्यकता है।
- यह एक क्षेत्र में कुत्तों को स्थानांतरित किये बिना मानव और आवारा कुत्तों के संघर्ष से नपिटने के तरीके पर दशिया-नरिदेश प्रदान करता है।
- यह पशु कल्याण सुनश्चिति करने, ABC कार्यक्रमों को चलाने में शामिल कुररता को संबोधित करने पर भी महत्त्व देता है।

रेबीज़

■ परिचय:

- रेबीज़ एक वैक्सीन द्वारा रोकथाम योग्य ज़ूनोटिक वशिषणु जनति बीमारी है।
 - एशिया और अफ्रीका में 95% से अधिक मानव मौतें इसके कारण होती हैं और यह बीमारी अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर देखी गई है।

■ कारण:

- यह [राइबोनयुकलिक एसडि](#) (RNA) वायरस के कारण होता है जो पागल जानवर (कुत्ते, बलिली, बंदर आदि) की लार में मौजूद होता है।
- यह एक संक्रमित पशु के काटने के बाद अनविर्य रूप से फैलता है जसिसे घाव में लार और वायरस का प्रवेश होता है।
 - WHO के अनुसार, कुत्ते मानव रेबीज़ से होने वाली मौतों का मुख्य स्रोत हैं, जो मनुष्यों को रेबीज़ के सभी संचरणों में 99% तक योगदान देते हैं।

■ भारत में रेबीज़ की स्थिति:

- भारत रेबीज़ के लिये स्थानिक है एवं वशि्व में रेबीज़ से होने वाली कुल मौतों में 36% मौतें भारत में देखी गई हैं।
- WHO के अनुसार, भारत में रपिर्ट किये गए रेबीज़ के लगभग 30-60% मामले और मौतों में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, क्योंकि जानवर के काटने के कारण बच्चों में उत्पन्न होने वाले लक्षणों की पहचान करना मुश्किल है और इसकी रपिर्ट भी नहीं की जाती है।

■ उपचार:

- रेबीज़ को पालतू जानवरों का टीकाकरण कर, वन्य जीवन से दूर रखकर तथा लक्षणों के शुरू होने से पहले संभावित जोखिम को चकितिसा देखभाल प्रदान करके रोका जा सकता है

■ रेबीज़ नियंत्रण से संबंधित पहल:

- वैश्विक:
 - यूनाइटेड अर्गेंस्ट रेबीज़ फोरम: UAR फोरम वभिन्न संगठनों, मंत्रालयों एवं देशों के वैश्विक वशिषज्जों को एक साथ लाता है ताकि वे वर्ष 2030 तक रेबीज़ के कारण होने वाली मृत्यु को शून्य तक लाने के प्रयासों को सुवधिजनक बनाने हेतु वशिषिट उद्देश्यों एवं गतिविधियों की दशिया में काम कर सकें।
- भारत की पहल:
 - वर्ष 2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज़ के उनमूलन के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan For Dog Mediated Rabies Elimination- NAPRE): NAPRE को [राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र \(NCDC\)](#) द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया था।
 - रेबीज़ के उनमूलन हेतु इसका दृष्टिकोण वशि्व स्वास्थ संगठन एवं रेबीज़ नियंत्रण के वैश्विक गठबंधन (GARC) जैसी कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सफिरशियों पर आधारित है।

नबिकरषः

- भारत **वन हेल्थ नेटवर्क** बनाने के ललतल उत्सुक है, यह न केवल रेबीज़ बलूकपलशु और मानव सवास्थल तथा अनूतू प्रसंगकल कषेत्रों के बीकू बेहतर समनूतू एवं संचार के माधूतू से मानव-पशु-परूतूवरण इंटरफेस पर कई सवास्थल जोखमलों कल नगरलनी तथा सवास्थल प्रणाली को भी मज़बूत करेगा ।

सूतूतः पी.आई.बी.

वशल्व जनसंखूतू सथतरलरलरलरतः UNFPA

प्रललमलस के लतूतः

UNFPA, प्रजनन दर, जनसांखूतूकल ललभांश, सततू वकलस लकषूतू, ECOSOC

मेनूस के लतूतः

वशल्व जनसंखूतू सथतरलरलरलरत

कूरूतू में कूरूतू?

हलल ही में **संयुक्त रलषटूर जनसंखूतू कूष (UNFPA)** ने वशल्व जनसंखूतू सथतरलरलरलरत **2023** जलरी कल है, जसलमें कलल गतू है कभलरत वरूष **2023** के मधूतू तक वशल्व कल सबसे अधकल आबलदी वललल देश बन जलएगा और भारत कल जनसंखूतू कून से भी अधकल हो जलएगी ।

- वशल्व जनसंखूतू सथतरलरलरलरत प्रतूतूवरूष प्रकलशतल होती है जो वशल्व जनसंखूतू और जनसांखूतूकल में वकलसलतूतूक प्रवृत्तलतू को शलमलल करतू है एवं उनकल वशल्लेषण करतू है, सलथ ही वशलषलट कषेत्रों, देशों और जनसंखूतू समूहों तथा उनके समकष आने वलली वशलषलट कूनूतूतूतू पर प्रकलश डललतू है ।

DEMOGRAPHIC INDICATORS

	Population	15-64 years	65+	TFR	Life expectancy
India	1,428.6 mn	68%	7%	2.0	72.5 yrs
China	1,425.7 mn	69%	14%	1.2	79 yrs
World	8,045 mn	65%	10%	2.3	73.5 yrs

UNFPA's State of World Population Report 2023

रलरलरत कल मुखूतू वशलषतलतूतू:

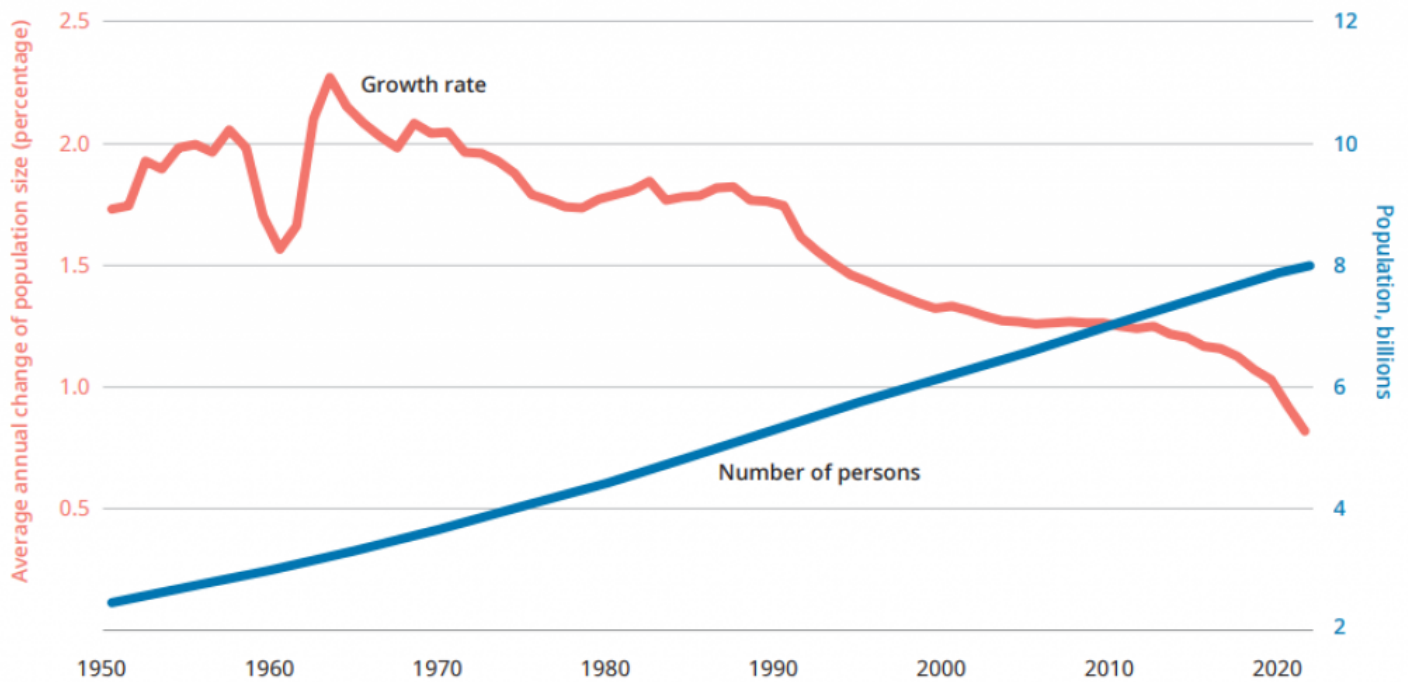
- जनसंखूतू अनुतूतूतू:
 - जुललई 2023 तक कून कल 142.57 करोड़ जनसंखूतू कल तुलनल में भारत कल जनसंखूतू 142.86 करोड़ तक पहुँकूने कल अनुतूतूतू है ।
 - भलरत कल **25%** जनसंखूतू **0-14 वरूष** आयू वरूग में, **18%** जनसंखूतू **10-19 वरूष** आयू वरूग में, **26%** जनसंखूतू **10-24 वरूष** आयू वरूग में, **68%** जनसंखूतू **15-64 वरूष** आयू वरूग में और **7%** जनसंखूतू **65 वरूष** से ऊपर कल आयू कल है ।

- अपने एशियाई पड़ोसी देश की तुलना में भारत में 29 लाख अधिक लोग होंगे।

- संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 340 मिलियन है।

■ धीमी जनसंख्या वृद्धि:

- अनुमानित वैश्विक आबादी के एक-तहाई से अधिक होने के बावजूद भारत और चीन दोनों में जनसंख्या वृद्धि धीमी रही है।



■ प्रजनन दर:

- भारत की कुल **प्रजनन दर** 2 आँकी गई थी, जो विश्व औसत 2.3 से कम है।
- विकसित क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.5, कम विकसित क्षेत्रों में 2.4 और कम विकसित देशों में 3.9 होने का अनुमान है।

■ जीवन प्रत्याशा:

- एक भारतीय पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष अनुमानित है।
- वैश्विक स्तर पर औसतन पुरुषों के लिये जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष तथा महिलाओं के लिये 76 वर्ष होने का अनुमान है।
- विकसित क्षेत्रों हेतु पुरुषों के लिये औसत जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष और महिलाओं के लिये 83 वर्ष अनुमानित की गई थी, जो कसबसे अधिक है।
- कम विकसित क्षेत्रों के लिये पुरुषों हेतु 70 वर्ष और महिलाओं के लिये 74 वर्ष है, जबकि कम विकसित देशों में यह पुरुषों के लिये 63 वर्ष और महिलाओं हेतु 68 वर्ष अनुमानित है।

■ लैंगिक अधिकार:

- वगित 12 महीनों में 18% महिलाओं द्वारा अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की सूचना दी गई थी, जबकि 66% महिलाओं ने भारत में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारों पर स्वयं नरिणय लिया था।
- 80% से अधिक महिलाओं के पास अपने स्वयं के स्वास्थ्य सेवा के बारे में नरिणय लेने में कुछ सहयोग था।

■ जनसंख्या वृद्धि संकेंद्रण:

- वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक आठ देशों - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मसिर, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंज़ानिया में संकेंद्रण होगा।

अनुशंसाएँ:

- भारत के पास 25 वर्ष से कम आयु की लगभग आधी आबादी के साथ **जनसांख्यिकीय लाभांश** से लाभान्वित होने का एक समयबद्ध अवसर है। हालाँकि मुख्य लक्ष्य महिलाओं को अधिक अधिकार देना है ताकि वे परिवार नियोजन में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें।
- स्थायी भवष्य का नरिधारण करने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक लैंगिक समानता है, जो महिला सशक्तीकरण तथा लड़कियों और महिलाओं हेतु अधिक शारीरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी।
- उच्च जनसंख्या के बावजूद संपन्न और समावेशी समुदायों का नरिमाण किया जा सकता है यदि राष्ट्र मौलिक रूप से परिवर्तन करने के इच्छुक हैं जो इस बात पर नरिभर करेगा कि वे जनसंख्या परिवर्तन को लेकर किस प्रकार को दृष्टिकोण रखते हैं एवं तैयारी करते हैं।
- उच्च प्रजनन क्षमता वाले देशों को शिक्षा और परिवार नियोजन के माध्यम से सशक्तीकरण, आर्थिक विकास एवं मानव पूंजी विकास के रूप में भारी लाभांश प्राप्त करने हेतु जाना जाता है।

- सभी सरकारों को मानवाधिकारों को बनाए रखना चाहिये, पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मज़बूत करना चाहिये, सक्रिय एवं स्वस्थ उमर को बढ़ावा देना चाहिये, प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये, साथ ही जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को कम करना चाहिये।

भारत हेतु अवसर और चुनौतियाँ:

■ अवसर:

○ जनसांख्यिकीय लाभांश:

- भारत की जनसंख्या एक बड़े कार्यबल के संदर्भ में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जो आर्थिक विकास को चलाने में मदद कर सकती है।
- भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की है, जो कामकाज़ी या काम करने में सक्षम आबादी में महत्वपूर्ण योगदान करती है।
- यह नशिचति रूप से एक जनसांख्यिकीय लाभांश है जब दुनिया के बहुत सारे उन्नत देश अपनी जनसंख्या के वृद्ध होने की चुनौती का सामना कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से कार्यशील लोगों की संख्या कम हो जाती है।

○ व्यवसायों और नवाचार को आकर्षित करने में मदद:

- बड़ी आबादी के साथ भारत एक विशाल और विकसित होते उपभोक्ता बाज़ार का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें नविश को आकर्षित करने और घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने की क्षमता है।
- वननिर्माण कार्य के लिये चीन की तुलना में अब भारत पश्चिमी देशों से बड़े व्यवसायों को आकर्षित करने के लिये अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है।
- विशाल और विविधतापूर्ण आबादी नवाचार का स्रोत व केंद्र दोनों हो सकती है, क्योंकि यह विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को एक एकजुट करती है।

○ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता:

- बढ़ती जनसंख्या के साथ भारत को संभवतः वैश्विक मंच पर अधिक शक्ति और प्रभाव का दावा करने में मदद मिल सकती है।
- भारत [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद](#) में स्थायी सदस्य होने का दावा कर सकता है।

○ ग्लोबल साउथ का नेतृत्वकर्ता:

- सबसे अधिक आबादी वाले देश का दर्जा भारत को [ग्लोबल साउथ](#) में नेतृत्व का दावा करने में भी मदद करेगा जिसके लिये वह वर्ष 2022 में [G20 की अध्यक्षता](#) के बाद से प्रयासरत है।

■ कमियाँ:

○ बेरोज़गारी और सामाजिक समस्याएँ:

- उदाहरण के लिये सविलि सेवा क्षेत्र में मात्र 700 पदों के लिये लगभग 6.5 लाख उम्मीदवार प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जबकि रेलवे में कुछ सौ नमिन-श्रेणी की नौकरियों के लिये हजारों युवा प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
 - उच्च बेरोज़गारी के रूप में भारत की युवा आबादी एक बड़ी समस्या का सामना कर रही है, जो **आवश्यक रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण और भी बदतर हो गई है।**

○ बेरोज़गारी न केवल आर्थिक तनाव की ओर ले जाती है बल्कि सामाजिक समस्याओं में भी वृद्धि करती है, खासकर **तबज़ब कामकाज़ी उम्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उपयुक्त रोज़गार पाने में असमर्थ होता है।**

○ गरीब श्रम बल की भागीदारी:

- भारत की विशाल जनसंख्या विशेष रूप से महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में कमी है।
- वर्ष 2021 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 19% थी, जो विश्व औसत 25.1% से कम है और लंबे समय से इसमें गिरावट देखी जा रही है।
 - भारत के प्रधानमंत्री का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 50% महिला कार्यबल सुनिश्चित करना है।

○ गरीबी:

- भारत की आबादी में गरीबी में रहने वाले लोगों की एक महत्वपूर्ण संख्या शामिल है, जो असमानता, अपराध और सामाजिक अशांति जैसे मुद्दों को बढ़ा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA):

■ परिचय:

- यह [संयुक्त राष्ट्र महासभा \(UN General Assembly\)](#) का एक सहायक अंग है जो इसके यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है।
- UNFPA का जनादेश [संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद \(Economic and Social Council- ECOSOC\)](#) द्वारा स्थापित किया गया है।

■ स्थापना:

- इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था, इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ।
- इसे वर्ष 1987 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम UNFPA (जनसंख्या गतिविधियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कोष) को भी बरकरार रखा गया।

■ उद्देश्य:

- UNFPA स्वास्थ्य (SDG3), शिक्षा (SDG4) और लैंगिक समानता (SDG5) पर [सतत विकास लक्ष्यों](#) से निपटने के लिये सीधे काम

करता है।

■ नधिः

- UNFPA को संयुक्त राष्ट्र के बजट का समर्थन प्राप्त नहीं है, इसके बजाय यह पूरी तरह से दाता सरकारों, अंतर-सरकारी संगठनों, नज्ी क्षेत्र, फाउंडेशन और व्क्तयों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्थित है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. किसी भी देश के संदर्भ में नमिनलखिति में से कसिे उस देश की सामाजकि पूंजी (सोशल कैपिटल) के भाग के रूप समझा जाएगा? (2019)

- (a) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात
- (b) इसके भवनों, अन्य आधारति संरचना और मशीनों का स्टॉक
- (c) कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आकार
- (d) समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत को "जनसांख्यिकीय लाभांश" वाला देश माना जाता है। इसकी वजह है (2011)

- (a) इसकी 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में उच्च जनसंख्या
- (b) इसकी 15-64 वर्ष के आयु वर्ग की उच्च जनसंख्या
- (c) इसकी 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की उच्च जनसंख्या
- (d) इसकी कुल उच्च जनसंख्या

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. जनसंख्या शकिषा के प्रमुख उद्देश्यों की वविचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर वसितृत प्रकाश डालयि। (2021)

प्रश्न. "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धिको नयितरति करने की कुंजी है।" चर्चा कीजयि। (2019)

प्रश्न. समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजयि ककि्या बढ़ती हुई जनसंख्या नरिधनता का मुख्य कारण है या नरिधनता जनसंख्या वृद्धिका मुख्य कारण है। (2015)

स्रोत: डाउन टू अर्थ